

## सरकारी प्रतभूतियों के लाभांश में गिरावट

### प्रलिस के लिये:

[सरकारी प्रतभूति](#) (जी-सेक), ऋण घटक, [बॉण्ड यीलड](#)

### मेन्स के लिये:

जी-सेक की अवधारणा और उनका महत्त्व, वैकल्पिक नविश विकल्पों के साथ जी-सेक की तुलना

## चर्चा में क्यों?

भारत में 10 वर्ष की [सरकारी प्रतभूति](#) (जी-सेक) बेंचमार्क के लाभांश/यीलड में गिरावट देखी गई है, जिससे [खुदरा नविशकों](#) के समक्ष उनकी नविश रणनीति के संदर्भ में चुनौती उत्पन्न हो गई है।

- [भारतीय रजिर्व बैंक](#) (Reserve Bank of India- RBI) ने [खुदरा नविशकों](#) हेतु सरकारी प्रतभूति बाज़ार की सुविधा उपलब्ध कराई है, हालाँकि उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है।

## सरकारी प्रतभूतियों के लाभांश में गिरावट का कारण:

- [ऋण म्युचुअल फंड कराधान में बदलाव](#) के बाद मार्च 2023 की शुरुआत में बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी प्रतभूति (G-sec) का लाभांश 7.4% से गिरकर 6.9% (मई 2023) हो गया है। यह अभी लगभग 6.96-6.99% की दर से कारोबार कर रहा है।
  - ऋण म्युचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना में इंडेक्सेशन के लाभ को हटा दिया गया है।
- [ऋण म्युचुअल फंड कराधान में बदलाव](#), [रेपो दर पर RBI के नरिणय](#) और [मुद्रास्फीति](#) में गिरावट जैसे विभिन्न कारकों ने सरकारी प्रतभूति लाभांश में गिरावट दर्ज की है।

## जी-सेक में खुदरा नविशकों की कम भागीदारी का कारण:

- [नविशक मार्गदर्शन का अभाव](#):
  - खुदरा नविशकों को [सरकारी बॉण्ड](#) में नविश करना जटिल लगता है, साथ ही प्रक्रिया के परिचालन के लिये प्रायः बचौलियों के माध्यम से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
- [सीमति तरलता](#):
  - जी-सेक बाज़ार में तरलता की कमी है, जिससे [खुदरा नविशकों](#), जब वे अपनी प्रतभूतियों को बेचना चाहते हैं, के लिये [द्वितीयक बाज़ार में खरीदार खोजना चुनौतीपूर्ण](#) हो जाता है।
    - तरलता की इस कमी के परिणामस्वरूप नविशक अपने नविश को फँसा हुआ महसूस करते हैं।
- [नविश में जटिलता](#):
  - खुदरा नविशक, विशेष रूप से [असूचित प्रतभागियों](#) को सरकारी प्रतभूति की नविश प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण लग सकती है और [सावधि जमा जैसे अधिक सरलीकृत नविश विकल्प पसंद](#) आ सकते हैं।
    - RBI रटिल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म [सूचित नविशकों के लिये फायदेमंद](#) है, लेकिन यह उन [असूचित प्रतभागियों के लिये नहीं](#) है, जिन्हें सरल नविश प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
- [कम व्यापार पूंजी](#):
  - सरकारी प्रतभूति के लिये [द्वितीयक बाज़ार में व्यापार की मात्रा अपेक्षाकृत कम](#) रही है, जिस कारण [खुदरा नविशकों का आकर्षण कम](#) हो गया है।
- [वैकल्पिक नविश विकल्प](#):
  - खुदरा नविशक नविश के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं जैसे [सावधि जमा](#) या नए बॉण्ड, [NCD \(गैर-परिवर्तनीय डबिंचर\)](#) और [डाकघर जमा योजना](#), जिसमें ब्याज दरों में वृद्धि देखी गई है।

## सरकारी प्रतभूतियाँ:

### परिचय:

- सरकारी प्रतभूतियाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है।
- सरकारी प्रतभूतियाँ एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिये जनता से धन उधार लेने के लिये जारी किया जाता है।
  - ऋणकर्त्ता एक वित्तीय साधन है जो जारीकर्त्ता द्वारा एक निर्दिष्ट तथि पर धारक को एक नश्चिती राशिका भुगतान करने के लिये एक संवदात्मक दायित्व का प्रतनिधित्व करता है, जसि मूलधन या अंकति मूल्य के रूप में जाना जाता है।
- यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतभूतियाँ अल्पावधि (आमतौर पर राजकोषीय बलि कहलाती हैं, एक वर्ष से कम की मूल परपिक्वता के साथ- वर्तमान में तीन अवधियों में जारी की जाती हैं, अर्थात् 91-दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घावधि (जसि आमतौर पर सरकारी बॉण्ड या दिनांकति कहा जाता है, एक वर्ष या उससे अधिक की मूल परपिक्वता वाली प्रतभूतियाँ) की होती हैं।
- भारत में केंद्र सरकार राजकोषीय बलि और बॉण्ड या दिनांकति प्रतभूतियाँ दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बॉण्ड या दिनांकति प्रतभूतियाँ जारी करती है, जनिहें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।
- जी-सेक में व्यावहारिक रूप से डफॉल्ट का कोई जोखमि नहीं होता है और इसलिये जोखमि मुक्त गलिट-एज्ड उपकरण कहलाते हैं।
  - गलिट-एज सक्ियोरटिज, उच्च-श्रेणी के नविश बॉण्ड हैं जो सरकारों और बड़े नगिमों द्वारा धन उधार लेने के साधन के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं।
- RBI, धन की आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिये जी-सेक की बकिरी या खरीद के लिये ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) आयोजित करता है।
  - RBI, एक प्रक्रिया के अंतरगत तरलता को हटाने के लिये जी-सेक बेचता है और एक अन्य प्रक्रिया के अंतरगत तरलता को बढ़ाने के लिये जी-सेक खरीदता है।

### बॉण्ड लाभांश:

- बॉण्ड लाभांश वह रटिरन है, जो एक नविशक को बॉण्ड पर मलित है। उपज की गणना के लिये गणतीय सूत्र बॉण्ड के वर्तमान बाज़ार मूल्य से वभिजति वार्षिक कूपन दर है। मूल्य और लाभांश वपिरीत रूप से संबंधति हैं, जैसे-जैसे एक बॉण्ड की कीमत बढ़ती है, इसके वपिरीत ही इसका लाभांश घट जाता है।

### बॉण्ड:

- यह धन उधार लेने का एक साधन है। कसिी देश की सरकार द्वारा या कसिी कंपनी द्वारा धन एकत्रित करने के लिये एक बॉण्ड जारी किया जा सकता है।

### कूपन दर:

- यह बॉण्ड जारी करने वालों द्वारा बॉण्ड के अंकति मूल्य पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर है।

## जी-सेक के प्रकार:

### ट्रेज़री बलि (T-bills):

- ट्रेज़री बलि शून्य कूपन प्रतभूतियाँ हैं, इस कारण कोई ब्याज प्रदान नहीं करते हैं। इसके अतरिकित उनहें छूट पर जारी किया जाता है और परपिक्वव होने पर अंकति मूल्य पर भुनाया जाता है।
- वर्ष 2010 में भारत सरकार ने RBI के परामर्श से भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिये CMBs के रूप में जाना जाने वाला एक नया अल्पकालिक साधन प्रारंभ किया। CMBs में ट्रेज़री बलि सामान्य प्रकृत्तिका होता है लेकिन यह 91 दिनों से कम की परपिक्वता अवधिके लिये जारी किया जाता है।

### दिनांकति जी-सेक:

- दिनांकति जी-सेक, प्रतभूतियाँ हैं जो एक नश्चिती या फ्लोटगि कूपन (ब्याज दर) रखती हैं, जसिका भुगतान अंकति मूल्य पर अर्द्ध-वार्षिके आधार पर किया जाता है। सामान्यतः दिनांकति प्रतभूतियों की अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है।

### राज्य विकास ऋण (SDLs):

- राज्य सरकारें भी बाज़ार से ऋण लेती हैं जनिहें SDL कहा जाता है। SDL, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकति प्रतभूतियों के लिये आयोजित नीलामी के समान सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी दिनांकति प्रतभूतियाँ हैं।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 'खुला बाज़ार प्रचालन' कसिे नरिदषिट करता है? (2013)

- अनुसूचति बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना
- वाणजियिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार कषेत्रों को ऋण देना
- RBI द्वारा सरकारी प्रतभूतियों का क्रय और वकिरय
- उपरयुक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है कति किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं।
2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेज़री बिल) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहीं करती।
3. कोष-पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/falling-yield-on-government-securities>

